23 April
PG Sem - IV

11. पिछड़ा वर्ग आन्दोलन (BACKWARD CLASS MOVEMENT)

समकालीन भारत की एक प्रमुख विशेषता संरचनात्मक असमानता है। सम्पूर्ण भारतीय जनसंख्या जातिगत आधार पर अनेक भागों में बँटी हुई है। विभिन्न जातियों के मध्य उच्चता और निम्नता का संस्तरण पाया जाता है। साथ-ही-साथ अलग-अलग जातियों की प्रतिष्ठा, सामाजिक स्थिति, शक्ति और सुविधाएँ एक-दूसरे से भिन्न तथा पूर्व परिभाषित एवं पूर्व निर्धारित रही हैं। इस जातिगत विभाजन ने सामाजिक और आर्थिक रूप से उच्च जाति की तुलना में अन्य जातियों को पिछड़ा कर दिया। निम्न जाति जो हरिजन या भारतीय संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति के नाम से जानी जाती हैं इनकी स्थिति अत्यन्त दयनीय रही। इनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए भारतीय संविधान ने आरक्षण की विशेष व्यवस्था प्रारम्भ की। राजनीतिक आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्र में हरिजन समुदाय को विशेष सुविधाएँ प्रदान की गयीं।

11.1 पिछड़ा वर्ग आन्दोलन का अर्थ (Meaning of Backward Class Movement)

भारतीय संविधान ने राज्य के लिए यह नीति भी निर्धारित की, "भारत में निवास करने वाले सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े अन्य वर्गों" के उत्थान के लिए भी प्रयास करेगा। संविधान ने पिछड़े वर्ग शब्द का प्रयोग किया, न कि पिछड़ी जाति का। कालान्तर में पिछड़े वर्ग की समस्याओं का हल ढूँढ़ने के लिए आयोग की स्थापना की गयी। इस प्रकार का प्रथम आयोग काका कालेलकर के नेतृत्व में 1953 में बनाया गया। कई राज्यों में भी पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित आयोग बनाये गये जैसे– गुजरात में बक्सी आयोग। 1978-80 में मण्डल आयोग ने पिछड़े वर्ग की समस्या का गहन विश्लेषण करके सुझाव प्रस्तुत किये हैं।

काका कालेलकर के नेतृत्व में स्थापित प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित चार सूत्रों के आधार पर पिछड़े वर्ग को परिभाषित करने का प्रयास किया:

1. हिन्दू धर्म के जाति प्रधान समाज में जिनका सामाजिक स्थान न हो।
2. वे जातियाँ या वर्ग जिनमें सामान्यतः शिक्षा का प्रचार-प्रसार कम हो।
3. सरकारी सेवाओं में अपेक्षाकृत कम प्रतिनिधित्व हो।
4. आर्थिक पिछड़ापन हो।

1955 में काका कालेलकर ने आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके आधार पर उन्होंने विभिन्न जातियों को पिछड़ा वर्ग घोषित किया और उन्हें उन राज्यों में नौकरी में विशेष सुविधा प्रदान करने की सिफारिश की। 1977 में कांग्रेस के स्थान पर जनता पार्टी का शासन केन्द्र में हुआ और कुछ प्रदेशों में भी जनता पार्टी की सरकारें बनीं। सर्वप्रथम बिहार ने पिछड़ी जाति को 26% आरक्षण प्रदान किया। तमिलनाडु में 50% और उत्तर प्रदेश में 16% आरक्षण का अनुमोदन किया गया। गुजरात और बिहार में आरक्षण की व्यवस्था को लेकर व्यापक आंदोलन किये गये। मण्डल आयोग की स्थापना के द्वारा सम्पूर्ण भारतीय स्तर पर पिछड़े वर्ग की पहचान और नौकरी में आरक्षण का अनुमोदन किया गया। वर्तमान समय में आरक्षण का

Scanned with CamScanner

आन्दोलन अनुसूचित जाति को आरक्षण की सुविधा बढ़ाये जाने की अवधि से सम्बन्धित था। यह आरक्षण से सम्बन्धित नवीनतम आन्दोलन है। जाति के स्थान पर आर्थिक पिछड़ापन को आधार बनाकर अन्य वर्गों, अन्य जातियों को भी आरक्षण की सुविधा प्रदान करना चाहता है।

विशेषताएँ (Characteristics)

पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित आंदोलन की प्रमुख विशेषताएँ और मुद्दे निम्नलिखित हैं।

(1) यह आन्दोलन भारतीय सामाजिक संरचना में उच्च जाति के प्रभुत्व का विरोधी है।

(2) यह आन्दोलन पिछड़ी जाति के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण की माँग करके कर्मचारी तन्त्र में पिछड़ी जाति की जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व का अनुमोदन करता है।

(3) यह आन्दोलन जनवादी राजनीति संरचना में संख्या की महत्ता पर बल देता है। अर्थात् पिछड़ी जाति के लोग जो संख्या की दृष्टि से उच्च जाति से अधिक हैं उन्हें राजनैतिक सत्ता और शक्ति के उपयोग का अधिक अवसर मिलना चाहिए।

(4) यह आन्दोलन राजनीति से प्रेरित आंदोलन है, जो न केवल सरकारी नौकरी में वरन् राजनीतिक सत्ता के नियन्त्रण में पिछड़ी जाति को उचित स्थान देना चाहता है।

(5) यह आंदोलन ग्रामीण आर्थिक संरचना, विशेष रूप से भूमि के सम्बन्ध में होने वाले परिवर्तन का भी प्रतीक है। अर्थात् गाँवों में उच्च जाति या तो अनुपस्थित भूमि स्वामी के रूप में भूमि का नियन्त्रण रखता है या गैर कृषि व्यवस्था में संलग्न होता जा रहा है। पिछड़ी जाति के सदस्य भूमि के वास्तविक स्वामी हैं या कृषक मजदूर के रूप में कृषि व्यवसाय से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित हैं। अतः पिछड़ी जाति के लोग अपनी इस नवीन आर्थिक स्थिति के अनुरूप विकास कार्यक्रमों, सरकारी नौकरी और राजनीतिक सत्ता का और अधिक उपभोग करना चाहते हैं।

यह आन्दोलन राजनीतिक सत्ता के उतार चढ़ाव से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है। कुछ राजनीतिक दल पिछड़ी जातियों के हित संरक्षण से सम्बन्धित हैं। जबकि अन्य दल उच्च जाति या हरिजन जाति का मुख्य रूप से समर्थन करते हैं। परिणामतः चुनावी राजनीति और सरकार के उत्थान पतन में पिछड़े वर्ग की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है।

11.2 दक्षिण भारत का पिछड़ा वर्ग आन्दोलन (Backward Class Movement of South India)

प्रो० राव तथा चन्द्रशेखर भट्ट ने दक्षित भारत की पिछड़ी जातियों में हुए आंदोलनों का विश्लेषण समाज सुधार आन्दोलन की अवधारणा के प्ररिप्रेक्ष्य में किया है। यद्यपि दोनों विचारकों के दृष्टिकोण में थोड़ी भिन्नता है फिर भी दोनों के वर्ण्य-विषय एवं अभिप्राय काफी मिलते जुलते हैं।

राव ने दक्षिण के पिछड़े वर्ग के आन्दोलन एवं निग्रो लोगों द्वारा चलाये जाने वाले अश्वेत आन्दोलनों के बीच समानता सूत्र खोजने का प्रयास किया है। राव की धारणा है कि इस प्रकार के आन्दोलनों में स्वरूप एवं सभ्यता के तर्क पर आधारित विश्लेषण किये जाने चाहिये। उनकी दृष्टि में यद्यपि संयुक्त राज्य एवं भारत की सामाजिक आर्थिक स्थितियाँ काफी असमान हैं फिर भी दोनों ही देशों में हुए आन्दोलनों में सूक्ष्म पर सादृश्य स्थापित होते हैं।

राव का कहना है कि 'अश्वेतों' तथा पिछड़े वर्ग के लोगों की सामाजिक स्थिति में एक बहुत बड़ी समानता का बिन्दु दोनों में तुलनात्मक अभाव बोध पाया जाना है। ऐतिहासिक

Scanned with CamScanner